विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत

935. **श्री अजीत जोगी** :

श्री मूलचन्द मीणा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकसित देशों की तुलना में भारत में बिजली की वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत वृद्वि या कमी हुई हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में तापीय और जल विद्युत दोनो क्षेत्रों में किस सीमा तक अतिरिक्त बिजली के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया गया हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी और सरकारी और सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत ताप, जल, गैस व परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) भारत में वर्ष 1993-94 के दौरान प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत 299 कि.वा. प्रति घंटा थी। कुछ विकसित देशों में वर्ष 1992 के दौरान प्रति व्यक्ति विद्युत संलग्र विवरण में दर्शाई गई हैं। (नीचे देखिए)

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान देश में प्रति व्यक्ति खपत मे प्रतिशत वृद्वि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार है:-

वर्ष	प्रति व्यक्ति खपत	प्रतिशत वृद्वि
1991-92	269.98	6.81
1992-93	283.10	4.86
1933-94	299.00	5.62

विवरण

वर्ष 1992 के दौरान विकासित देशों में वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत

देश का नाम	प्रति व्यक्ति खपत (कि.वा.आ. में)
कनाडा	18117
स्विटरजरैंड	8015
इटली	4525
आस्ट्रेलिया	9043
रूस	6659
ब्रिटेन	5933
अमरीका	12160
जापान	7192
जर्मनी	6627
फ्रांस	7140
स्वीडन	16655

(ग) सातवीं योजना के दौरान वास्तविक क्षमता अभिवृद्वि की तुलना में श्रेणीवार क्षमता-अभिवृद्वि लक्ष्य नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार हैं:-

श्रेणी	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत
ताप	15999.0	17104.20	106.9
न्यूक्लीय	705.0	470.0	66.6
जल विद्युत	5541.25	3827.44	69.0
जोड:	22245.25	21401.64	96.2

(घ) आठवीं योजना के दौरान क्षेत्र-वार और श्रेणीवार क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निम्नवत है:-

(आंकड़े मेगावाट में)

क्षेत्र	ज.वि.	ताप विद्युत	(गैस)	न्यूक्लीय	जोड़
केन्द्रीय	1405.0	6635.0	(2166.0)	880	8921.0
राज्य	2223.7	7963.0	(777.0)	-	10186.7
निजी	168.0	1454.0	(454.0)	-	1622.0
जोड़	3796.7	16053.0	(3347.0)	880	20729.7

Loans to M.S. shoes by Allahabad Bank

936. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item in the Asian Age dated 17th June, 1955 regarding sanction of Rs. 200 million as bridge loan to MA. M.S. Shoes Limited by Allahabad Bank;

(b) whether the above amount was sanctioned as alleged against an amount of Rs. 100 million approved by the Board.

(c) whether the loan has become sticky;

(d) if so, action taken by Government so far against the officials responsible; and

(e) if not, whether any rejoinder has been issued by the Bank or the Ministry?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) Reserve Bank of India (RBI) had called for explanation from Allahabad Bank regarding deficiencies/ irregularities observed in the sanction and utilisation of bridge loans to M/s. MS Shoes East Ltd. The reply received from the bank is being processed by RBI and a decision regarding action against the bank if any, would be taken by RBI thereafter.

Incentives for Increasing the Market Share of Cotton Textiles

937. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that cotton text"es are becoming fashionable and acceptable to the western markets and if so, what steps Government are taking to secure the market share for India;

(b) whether Government propose to give incentives to cotton growers and handloom weavers to increase the production; and

(c) if so, the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir. Government have been taking a number of steps to increase exports of textiles, including cotton textiles, such as sponsoring Buyer-Seller Meets, participation in fairs in major markets, releasing advertisements in foreign trade magazines, product development and quality upgradation through appropriate training programmes.

(b) and (c) The cotton Corporation of India is giving incentives to cotton growers for producing certified seeds of 80% and above genetic purity under their arrangement of seed production